जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 152 प्रभात उदयपुर, सोमवार 6 अप्रैल, 2026 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट व पुलों को निशाना बनायेंगे'

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज़ नहीं खोलने पर बड़े हमले की चेतावनी दी

- सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने बहुत आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे तथा बिज्र डे बनाया जाएगा।

वॉशिंगटन डीसी, 05 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहद तीखी भाषा में पोस्ट करते हुए ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 अप्रैल की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही ईरान पर दबाव बढ़ ा दिया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसा हमला होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

इससे पहले 21 मार्च को भी ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स को नष्ट कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े बिजली संयंत्र से होगी।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने बेहद आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा और ईरान को तुरंत होर्मुज़ खोलने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पहले ही उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस समय सीमा में समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका की ओर से कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शनिवार को भी कहा था कि समय खत्म हो रहा है और अगर ईरान ने कदम नहीं उठाया तो भयंकर हमला किया जाएगा।

अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव लगातार बढ़ ता जा रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑ होर्मुज़ को लेकर। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है और इसके बंद होने से वैश्विक स्तर पर असर पड़ रहा है।

रूस ने यूक्रेन पर रात भर में 286 ड्रोन दागे

कीव, 05 अप्रैल। यूक्रेन पर रूसी हमलों ने एक बार फिर हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। रात भर चले ड्रोन हमलों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तुर्की यात्रा के दौरान हुए इन हमलों में कई शहरों को निशाना बनाया गया, जिनमें निकोपोल और सूमी शामिल हैं। हमलों से रिहायशी इलाकों, बाज़ारों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा

- इन हमलों में 5 लोगों की मौत हुई व 30 घायल हुए।

स्थिति और गंभीर हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया एनबीसी के अनुसार, यूक्रेनी वायु सेना ने एक ऑनलाइन बयान में बताया कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 286 ड्रोन दागे, जिनमें से 260 को मार गिराया गया। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्जेंडर हंझा ने बताया कि निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के निकोपोल शहर में तीन महिलाओं और दो पुरुषों की मौत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वाइट हाउस के पास रात एक बजे गोलियाँ चली

सुरक्षा बलों ने आस-पास के इलाके की सघन तलाशी ली व वाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ाई

- अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को वाइट हाउस के उत्तर में स्थित लाफायेट के पास गोलियाँ चलने की सूचना मिली। अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नहीं मिला।

वॉशिंगटन, 05 अप्रैल। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में वाइट हाउस के पास रविवार तड़के गोलीबारी की घटना हुई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को आधी रात के बाद लाफायेट पार्क के पास गोलियां चलने की सूचना मिली थी। यह पार्क वाइट हाउस के ठीक उत्तर में स्थित है।

सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे पार्क और आसपास के इलाके की तलाशी ली। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र की पूरी जांच की गई, लेकिन फिलहाल कोई संदिग्ध नहीं मिला है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि सीक्रेट सर्विस की यूनिफॉर्म डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और पार्क पुलिस के साथ मिलकर एक संदिग्ध व्यक्ति और एक संभावित गाड़ी की तलाश कर रही है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना रात करीब एक बजे हुई। इसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और वाइट हाउस के उत्तर की सड़कों को सुरक्षित किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अधिकारी रात भर इलाके की छानबीन करते रहे।

वाइट हाउस के बेहद करीब गोलीबारी होने के बावजूद वहां का कामकाज सामान्य रहा। सीक्रेट सर्विस ने साफ किया कि राष्ट्रपति आवास के संचालन में कोई बाधा नहीं आई है। हालांकि, एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जांच के दौरान सुरक्षा घेरा बनाए रखने के लिए कई सड़कों को बंद कर दिया गया। इनमें एच स्ट्रीट एनडब्ल्यू, आई स्ट्रीट एनडब्ल्यू और 16वीं स्ट्रीट एनडब्ल्यू के कुछ हिस्से शामिल हैं। मौके पर मौजूद पत्रकारों और गवाहों ने बताया कि वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।

असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट- पवन खेड़ा

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने हिमंत सरमा की पत्नी पर विदेशों में सम्पत्ति छुपाने का भी आरोप लगाया

- पवन खेड़ा ने कहा कि रिंकी भइयां सरमा के नाम पर दुबई में दो सम्पत्तियाँ हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में इनका कोई उल्लेख नहीं है। चुनाव लड़ने वालों के लिए अनिवार्य है कि अपने परिवार की चल-अचल सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा हलफनामे में दें।

नई दिल्ली, 05 अप्रैल। असम विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया है। पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास विदेशों में संपत्तियां होने और इनका विवरण चुनावी हलफनामे में नहीं देने का आरोप भी लगाया है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कथित दस्तावेजों की फोटोकॉपी दिखाते हुए कहा कि रिंकी भुइयां सरमा के पास संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ-बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट हैं। यूएई का पासपोर्ट 14 मार्च 2022 को जारी हुआ और 13 मार्च 2027 तक वैध है, एंटीगुआ-बारबुडा का पासपोर्ट 26 अगस्त 2021 को जारी हुआ और 25 अगस्त 2031 तक वैध है, जबकि मिस्र का पासपोर्ट 13 फरवरी 2022 को जारी हुआ और 12 फरवरी 2029 तक वैध है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, ऐसे में यह मामला गंभीर जांच का विषय बनता है।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की राजनीति एक ओर जहां धार्मिक ध्रुवीकरण पर आधारित बताई जाती है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी के पास कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट होना कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके।

पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी भुइयां सरमा के नाम पर दुबई में दो संपत्तियां हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी और अपने परिवार की चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा हलफनामे में दे। ऐसे में इन संपत्तियों का जिक्र न होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

खेड़ा ने कहा कि अमेरिका के वायोमिंग में रिंकी भुइयां सरमा से जुड़ी एक कंपनी संचालित है, जिसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पवन खेड़ा पर 48 घंटे में मानहानि के मुकदमे करूंगा- हिमंत सरमा

गुवाहाटी, 05 अप्रैल। असम विधानसभा चुनावों के बीच रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सिरे से

- उन्होंने खेड़ा के आरोपों को दुर्भावना पूर्ण, मनगढंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

खारिज कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जारी अपने संदेश में कहा है कि पवन खेड़ा की रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरे असंतोष और घबराहट को दर्शाती है। जैसे-जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम मिया मुस्लिम नहीं, भारतीय मुस्लिम हैं'

विधानसभा चुनाव में असम के मुस्लिम समुदाय में बदलते राजनीतिक मूड के संकेत मिल रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रेल। जैसे - जैसे असम उच्च दांव वाले चुनाव की ओर बढ़ रहा है, राज्य का मुस्लिम समुदाय, जो राज्य की जनसंख्या का 30 प्रतिशत से अधिक है, का मूड आशा, चिंता और बदलती राजनीतिक निष्ठाओं का मिश्रित प्रतिबिंब प्रस्तुत कर रहा है। इनमें लगभग 12 प्रतिशत असमिया भाषी मुस्लिम हैं।

दशकों से, मुस्लिमों ने असम की चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है। वर्षों तक, मुस्लिम एकजुटता ने चुनावी नतीजों को आकार दिया, और कांग्रेस मुस्लिम समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर रही।

लेकिन, मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से एक नहीं रहे हैं। भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन ने उनमें अलग-अलग मतदान पैटर्न को जन्म दिया है।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के संस्थापक बदरुद्दीन अजमल के उदय ने बंगाली भाषी मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा एकजुट किया, जिससे पार्टी कुछ हिस्सों में एक मजबूत ताकत बनकर उभरी।

लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक महत्वपूर्ण मोड़ (टर्निंग पॉइन्ट) प्रस्तुत किया। अजमल को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब वे धुबरी सीट पर कांग्रेस नेता रक़ीबुल हुसैन से 10 लाख से अधिक वोटों से हार गए। इसे समुदाय के भीतर बदलते राजनीतिक मूड का संकेत माना गया। ये बदलाव पहचान, नागरिकता और प्रतिनिधित्व पर जारी बहसों के बीच हो रहे हैं।

- स्थानीय मुस्लिमों का कहना है, "हम इस चुनाव में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं चाहते। हम सब भाई हैं और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं।"
- यह भी कहा जा रहा है कि "बंगाली मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को बेदखल किया जा रहा है, घर हटाये जा रहे हैं।"

जमीनी स्तर पर भी ये तनाव और बदलाव गहराई से महसूस किए जा रहे हैं।

लोअर असम में, जहाँ बंगाली भाषी मुस्लिम ज्यादा हैं, वहां अनेक मतदाता एकता की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही शिकायत की भावना भी रखते हैं।

समरिया निर्वाचन क्षेत्र के गोरोइमारी में स्थानीय निवासी हुमायूं कबीर ने कहा, "हम इस चुनाव में किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं चाहते। हम सब भाई हैं और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमें एक होना होगा, हम असम और भारत में शांति चाहते हैं।"

साथ ही, वे पहचान के लेबल के खिलाफ भी हैं। उन्होंने कहा, "हम मिया मुस्लिम नहीं हैं, यह बहुत गलत है। हम भारतीय मुस्लिम हैं।" उन्होंने यह स्वीकार किया कि "पहले की तुलना में दंगे और अपराध कम हुए हैं," लेकिन यह भी कहा कि "बंगाली मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को बेदखल किया जा रहा है, घर हटाए जा रहे हैं।"

अब्दुल रईस ने कहा, "हमें सरकारी योजनाओं से लाभ मिलता है... हम लंबे समय से भारत में हैं। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं।" उनका यह कहना नागरिकता और वैधता को लेकर बार-बार उठने वाले मुद्दे को रेखांकित करता है।

कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर विभाजन की भावना भी बढ़ रही है।

इबीउल हुसैन कहते हैं, "हमें सरकार में बदलाव की आवश्यकता है। पहले मुस्लिम समुदाय एक साथ था, अब इसमें विभाजन है।" मिया शब्द का उल्लेख करते हुए, वे कहते हैं, "मिया मुस्लिमों को बांग्लादेशी मुस्लिम कहा जाता है। इससे समुदाय को नुकसान पहुंचा है।" उनका कहना है कि "असमिया भाषी मुस्लिम हमारे साथ हैं और कभी-कभी उनके साथ भी।"

इज़रायल के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 31 मई तक निलम्बित

नई दिल्ली, 05 अप्रैल। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच एअर इंडिया ने इज़रायल के लिए अपनी उड़ानें 31 मई तक निलंबित कर दी हैं।

एअर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन ने नई दिल्ली-तेल

- इज़रायल में रहने वाले 40 हजार भारतीयों की चिंता बढ़ी।

अवीव मार्ग पर उड़ानें 31 मई तक निलंबित कर दी हैं। उड़ानों के निलंबन ने इज़रायल में रहने वाले 40,000 से अधिक भारतीयों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो क्षेत्र में बढ़ ते तनाव से बचने या पेशेवर कारणों से भारत यात्रा करना चाहते हैं।

इज़रायल छोड़ने के इच्छुक भारतीयों को भूमिगत सीमा पार कर जॉर्डन या मिस्र जाना होगा। तेल अवीव में भारतीय मिशन उन लोगों की सहायता कर रहा है जो विभिन्न तरीकों से यात्रा करना चाहते हैं। दूतावास भारतीय समुदाय के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए है।

राजदूत जेपी सिंह और दूतावास की टीम ने इज़रायल में भारतीय श्रमिकों और छात्रों के साथ वर्चुअल चर्चा की और उनकी चिंताओं-परेशानियों को सुना। साथ ही उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पाकिस्तान से आई 60 करोड़ रूपए की हेरोइन पकड़ी

श्रीगंगानगर, 5 अप्रैल। बॉर्डर पर ड्रोन से आई 12 किलो हेरोइन बरामद की गई। संयुक्त कार्रवाई में पंजाब के 4 युवक पकड़े गए, जो पाकिस्तान से आई

- सुरक्षा बलों के सर्च अभियान में पंजाब के 4 युवक भी पकड़े गए, जो पाकिस्तान से ड्रोन से गिराई खेप उठाने के लिए आए थे।

इस खेप को उठाने पहुंचे थे। सीआईडी, पुलिस और बीएसएफ ने, सुरक्षा बलों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाकर तस्करी की कोशिश को रोका और आरोपियों से पूछताछ शुरू की।

जानकारी अनुसार, पाकिस्तानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आयात स्त्रोतों में विविधता की रणनीति ने तेल-गैस कीमतों में भारी वृद्धि को रोका

भारत कच्चे तेल का 88 प्रतिशत आयात करता है व यूरोप में गैस की कीमतों में 70 प्रतिशत वृद्धि हुई है

- होर्मुज़ और रेड सी में व्यवधान होने पर भारत ने शिपिंग कार्गो को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनः व्यवस्थित किया। हालांकि इससे यात्रा समय 30 प्रतिशत बढ़ा व फ्रंट लागत भी 40-60 प्रतिशत बढ़ गई।
- पेट्रोल और डीज़ल में सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती करके तथा निर्यात शुल्क लगाकर घरेलू बाजार में आपूर्ति को व्यवस्थित रखा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। भारत अपने कच्चे तेल का 88 प्रतिशत आयात करता है। फिर भी ईंधन और एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि क्यों नहीं हुई? जानिए उस अनोखी रणनीति के बारे में, जिसे भारत अपना रहा है।

पश्चिम एशियाई संकट के बीच यूरोप में गैस की कीमतों में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। इसके साथ ही, रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी।

ईरान युद्ध के बाद, ऊर्जा बाजार बेहद अस्थिर हो गए। यूरोज़ोन में महंगाई 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रशित हो गई, जिसमें ऊर्जा महंगाई का योगदान 4.9 प्रतिशत साल-दर-साल था। कच्चे तेल में 74 रूपए की वृद्धि, होर्मुज़ की खाड़ी का लगभग अवरुद्ध होना, और खाड़ी से एलपीजी की आपूर्ति में गिरावट से कई देशों में घरेलू मूल्य वृद्धि तेज होनी चाहिए थी। लेकिन भारत ने अब तक खुदरा प्रभाव को सीमित रखने में सफलता हासिल की।

भारत की संरचनात्मक निर्भरता काफी अधिक थी। इसके कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 88 प्रतिशत है, जबकि एलपीजी का 60 प्रतिशत आयात होता है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत होर्मुज़ के रास्ते आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवार सब्सिडी वाली एलपीजी पर निर्भर हैं, इसलिए इस निर्भरता का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ सकता था।

प्रारंभिक संकेत तनाव की ओर इशारा कर रहे थे, एलपीजी का आयात 3,22,000 मीट्रिक टन से घटकर 2,65,000 मीट्रिक टन हो गया, जबकि खाड़ी का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत रह गया। सामान्य प्रवाह में, इस तरह के झटके से खुदरा कीमतों में तेज वृद्धि होनी चाहिए थी।

लेकिन, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत ने पूरी तरह से बढ़ोतरी को रोक दिया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, और एलपीजी में केवल सीमित वृद्धि हुई। इसके अलावा, सरकार का दावा है कि उसने एलपीजी की कीमतों को स्थिर किया है, क्योंकि उसने इसकी आपूर्ति को आसान बनाने के उपाय किए हैं।

भारत की पहली प्रतिक्रिया आपूर्ति संबंधी अनुकूलन में थी, आयात स्रोतों में तेजी से विविधता लाई गई। यह अचानक किया गया समायोजन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद खरीद रणनीतियों का विस्तार था, जो संकट की स्थिति में विकल्प प्रदान करती थीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका एलपीजी का एक प्रमुख मार्जिनल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा, लगभग 22 लाख टन प्रति वर्ष के पूर्व-निर्धारित अनुबंधित वॉल्यूम के साथ, जो भारत के कुल आयात का लगभग 10 प्रतिशत है। यह अनुबंधित आधार बिना पुनः बातचीत के तेजी से आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

मुख्य बात यह है कि भारत की मजबूती संकट के बाद के तात्कालिक सुधार से नहीं आई, बल्कि एक विविध आयात पोर्टफोलियो से आई, जिसे तनाव के दौरान पुनः समायोजित किया जा सकता था, जिसमें अर्जेंटीना जैसे गैर-पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को शामिल किया गया।

इस आपूर्ति विविधीकरण को नौसैनिक और रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ पूरा किया गया।

होर्मुज़ और रेड सी दोनों में व्यवधान होने पर, शिपिंग कार्गो को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनः व्यवस्थित किया गया। लेकिन, इससे यात्रा समय लगभग 30 प्रतिशग बढ़ गया और फ्रेट लागत 40-60 प्रतिशत तक बढ़ गई, साथ ही बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई।

इन जोखिमों को कम करने के लिए भारत ने नौसैनिक और कूटनीतिक साधनों का उपयोग किया। ऑपरेशन संकल्प के तहत, भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की। साथ ही, कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से होर्मुज़ के चयनित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)